

"समसामयिक भारत-चीन संघर्ष तथा विश्व"

अनूप मिश्र

अतिथि सहायक प्राध्यापक,

(ललित नारायण मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय,

दरभंगा)

Email ID- anooppoet1992@gmail.com

सारांश:- बीते छः सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई । इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पहल की तरह से ही देखा गया । लेकिन बीते 2 महीनों से जो देशों के बीच सैन्य तथा युद्ध संघर्ष जैसी स्थिति आ गई है । दरअसल भारत क द्वारा पूर्वी लद्दाख में सड़क निर्माण भी एक वजह है क्योंकि साल 2018-19 की सलाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत-चीन सीमा 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है । इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बार्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO स्थिति बनी हुई है वह अंत्यत प्रश्रवाचक चिन्ह लगाता है कि आखिर क्या हो गया है कि दोनों को दिया गया है । इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी है । भारत-चीन सीमा विवाद का मूल कारण यही हो सकता है कि कई जानकार मानते है । सबसे विकट परिस्थिति तब प्रस्तुत हुआ जब भारत के 20 सैनिक चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गये तथा यह भी जानकारी मिली कि चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए लेकिन इसकी पुष्टि चीन आज तक नहीं किया । इसके अतिरिक्त चीन ने लगभग 10 सैनिकों को बंधक बनाया था जिसे स्वयं ही वह छोड़ दिया । दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण वैश्विक परिदृश्य में विभिन्न देशों के द्वारा अपना-अपना हित साधने का प्रयास किया जा रहा है । अभी कोरोना संकट के कारण अमेरिका लगातार चीन को इस संकट के लिए दोषी मानता है और कई अन्य देश भी चीन को ही दोषी मानते है । लेकिन चीन इन सब बातों से बेखौफ़ भारत, हांगकांग तथा ताइवान मामलों में उलझा हुआ है । जिससे अमेरिका को मौका मिल गया है कि चीन को सबक सीखाना जरूरी है लेकिन भारत के साथ चीन का संघर्ष एक विचारणीय विषय है जिसमें अमेरिका चीन की हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए

एक समूह को तैयार करने लगा है। परन्तु चीन को अलग-थलग किया जा सकता है यह आने वाला समय बताएगा।

प्रस्तावना:- भारत-चीन संबंधों में सहयोग कम संघर्ष का बोलबाला अधिक ही दिखाई देता है। यदि हमें समकालीन भारत-चीन संघर्ष को देखना है तो भारत-चीन संघर्ष के इतिहास पर एक नज़र डालने की आवश्यकता है। 1962 भारत-चीन युद्ध, ये लड़ाई एक महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। 1967 ई० नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गये थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग-अलग दावे करते हैं। 1975 ई० भारतीय सेना गस्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की ही तरह होगा। वजह साफ है भारत-चीन सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में सैनिकों की जान गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमती से सीमा विवाद को सुलझाने के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाये रखते हुए व्यापार और निवेश को लम्बे समय तक रहने दिया है। बीते छः सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई। इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पहल की तरह से ही देखा गया। इसलिए बीते 2 महीनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? भारत और चीन के बीच बात इतनी क्यों बिगड़ गई कि हिंसक संघर्ष तक पहुँच गई। प्रश्न यह उठता है कि क्या लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण ही चीन की चिंता का सबब है या बात कुछ और ही है? कुछ जानकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सड़क निर्माण एक वजह हो सकती है, पर एक मात्र वजह नहीं है। साल 2018-19 की सलाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत-चीन सीमा पर 3818 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत-चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों की असली वजह है। यदि इस संघर्ष को देखा जाय तो इस तनाव के पीछे कई मामले आपस में एक दुसरे जुड़े हैं। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत में जम्मू-कश्मीर के ख़ास दर्जे को खत्म कर दो नये केंद्रशासित प्रदेशों के नक्शे जारी किये तो चीन इस बात से खुश नहीं था

कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में अक्साई चीन भी था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-काश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला लिया। जिसके बाद 2 केन्द्रशासित प्रदेश बनाये गये- एक जम्मू-काश्मीर और दूसरा लद्दाख। चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया था विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू-काश्मीर से हटाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने का। भारत के फैसले का विरोध करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने उस वक्त कहा था - "चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत के अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है।" ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडी प्रोग्राम के हेड, हर्षपन्त का मानना है कि भारत के इस कदम को चीन अपने लिए एक खतरे पर देखता रहा है। काश्मीर पर भारत फैसले के बाद चीनी प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने कहा था, "हाल ही में भारत ने अपने घरेलू कानून में बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया है। भारत का यह कदम अस्वीकार है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी उठा। इस मुद्दे पर अनौपचारिक बैठक भी हुई लेकिन भारत ने वहां अपना पक्ष रखते हुए ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। जबकि चीन ने विरोध जताने के साथ-साथ अपना विरोध जारी रखा। अप्रैल में जब ठण्ड खत्म हुई तो दोबारा से उस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी।

अक्साई चीन के 38000 किलोमीटर के अलावा शक्सगाम (शक्षगाम घाटी) के 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर भी चीन का नियंत्रण है।

काराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शक्सगाम नदी के दोनों ओर शक्सगाम वादी फैला हुआ है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान का यह मानना था कि दोनों देशों की दोस्ती बढ़ेगी और साथ ही यह दलील दी थी कि चूंकि यहाँ पहले से अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं की थी लिहाजा पाकिस्तान को इसे चीन को सौंपने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी इलाके को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया था। आज चीन और पाकिस्तान यही बने काराकोरम हाइवे से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जो पश्चिमी काश्मीर के जरिए दोनों देशों को जोड़ता है। यदि लद्दाख में हो रहे प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है और उस इलाके में सैनिकों के लिहाज से इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, तो चीन काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ का जो

सीधा रास्ता जाता है, उसमें आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से भी चीन लद्दाख 'सीमा' पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

वर्तमान में भारत-चीन संघर्ष तथा इस संघर्ष में वैश्विक कुनबा:- बॉर्डर पर तनाव के चलते हाल ही में भारत ने कहा था कि वह झुकने वाला नहीं है और 1962 की तरह अब वह कमजोर नहीं है। यह ताकत भारत की भौगोलिक स्थितियों के कारण है या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण? जानिये कि चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत के साथ कौन से देश दोस्ती निभा सकते हैं और चीन के साथ कौन भारत-चीन संघर्ष के चलते जिस जगह भारत के भारत के 20 फौजियों की मौत हुई। यह वही जगह है, जहाँ करीब 60 साल पहले भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। एक बार फिर दोनों के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव है और संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि युद्ध की स्थिति में भारत का साथ कौन से देश देंगे। चीन के साथ कौन दोस्ताना निभायेगा। साल 1962 के युद्ध के समय चीन ने जीत की स्थिति में युद्धविराम घोषित किया था। इसी पारम्परिक आधार पर समझा जाता है कि भारत के खिलाफ चीन का पलड़ा भरी है, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन और में वाशिंगटन हुए ताज़ा अध्ययन को माने तो पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों में भारत बेहतर स्थिति में है। यानि हाल ही जहाँ संघर्ष हुआ, वहाँ भी भारत की भौगोलिक स्थिति मजबूत है। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात अंतरराष्ट्रीय संबंधों की है। युद्ध दो देशों के बीच जरूर होगा, लेकिन दो देश अकेले-अकेले नहीं लड़ेंगे। दुनिया के कई देश इन देशों में से किसी एक का साथ देंगे। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे समझना महत्वपूर्ण है। इस बारे में विश्लेषण करते हुए सीएनएन (CNN) की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हिमालय क्षेत्र में अपने ही बलबूते पर युद्ध कर सकता है, जबकि जबसे देखा कि चीन सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, तबसे भारत ने दुसरे देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने की दिशा कदम बढ़ाए। हाल के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका सैन्य लिहाज से और नजदीक आये हैं। वाशिंगटन ने यहाँ तक कहा कि 'भारत उसका प्रमुख रक्षा साथी' है दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर आपसी रक्षा संबंध हुए हैं। सीएनएन (CNN) की माने तो अब चीन के साथ हिमालय के क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में अमेरिका इंटेलेजेंस और निगरानी के तौर पर भारत को युद्ध भूमि के स्पष्ट व्यौरे देकर मदद कर सकता है। इस मदद से क्या होगा? बेलफर रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अगर चीन अपने अंदरूनी इलाकों से भारत की पहाड़ी सीमाओं तक अपनी फौजें लेकर आता है, तो अमेरिका अपनी तकनीकी के जरिये

भारत को अलर्ट करेगा । इससे मदद यह होगी की भारत हमले का जवाब देने के लिए अपनी तरफ से अतिरिक्त फौजों की तैयारी कर सकेगा ।

भारत के अलावा जापान, फ्रांस और आस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है । इसलिए भारत के साथ अभ्यास करने वाले पश्चिमी सैन्य दलों ने हमेशा भारत के दलों की क्रिएटिविटी और खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेने की क्षमता की भरसक तारीफ़ की है । चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत इन देशों से सहयोग की अपेक्षा करेगा ।

इस तरह के सैन्य अभ्यासों के हिस्साब से देखा जाय तो चीन के अब तक प्रयास काफी शुरूआती रहे हैं । हालाँकि पाकिस्तान और रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में काफी एडवांस्ड तकनीकों का प्रयोग हो चुका है । पाकिस्तान और रूस को चीन का रणनीतिक साथी मन जा रहा है लेकिन रूस अब तक तटस्थ रहा है । इस बार वह चीन का साथ दे सकता है या नहीं, इसे लेकर अब तक भी संशय ही है । इसके अलावा उत्तर कोरिया और मीडिल ईस्ट के किसी देश का चीन को मिलाने के भी क्या आस है ।

कोविड 19 महामारी के समय में अमेरिका ने चीन के खिलाफ बुने नैरेटिव मरण कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर वितंडावाद खड़ा किया है कि वैश्विक महामारी के लिए चीन जिम्मेदार है । ऐसे में अमेरिका के सहयोगी कई देश चीन के खिलाफ है । इन स्थितियों में अगर अमेरिका युद्ध में भारत का साथ खुलकर देता है, तो अमेरिकी प्रभव वाले कई देश चीन के खिलाफ खड़े नजर आयेंगे ।

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने मई आखिरी में एक नये अंतरराष्ट्रीय मंच डी 10 का आइडिया उछाला, जो असल में 10 लोक तांत्रिक शक्तियों का गठबंधन होगा । इस गठबंधन में जी० 7 के सात देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका तो शामिल होंगे ही साथ में भारत, दक्षिण कोरिया, और आस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा होंगे । इस गठबंधन का मकसद पूरी तरह से साझा लाभ और चीन के खिलाफ रणनीतिक एकजुटता बताया जा रहा है । ताज़ा स्थितियों में भारत इस प्रस्ताव को ठुकरायेगा नहीं, बल्कि इसमें सभी देशों से सैन्य सहयोग की सम्भावना भी ढूँढ सकता है । हाल ही में भारत ने चीन के 59 एप्प को बैन कर दिया जिसका अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया है ।

निष्कर्ष:- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत-चीन संघर्ष का ध्यान केवल भारत व चीन को ही नहीं वरन विश्व के कई देशों की भी है । दरअसल वर्तमान में कोरोना ने विश्व में जो कहर बरपाया है उससे कोई देश अछूता नहीं रह गया है तथा इस वैश्विक महामारी कोरोना की लाने का श्रेय विश्व के कई देश चीन को दे रहे हैं और इसी वजह से भारत-चीन संघर्ष में उन्हें एक मौका मिल गया है । इसके अतिरिक्त चीन द्वारा हांगकांग तथा ताइवान में जो फरमान जारी किया गया है इसके कारण भी पश्चिमी देश चीन को विस्तारवादी होने का आरोप लगा रहे है । यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यदि भारत और चीन के बीच संघर्ष युद्ध में तब्दील होता है तो रूस की रणनीति क्या होगी जो भारत का स्वाभाविक मित्र रहा है लेकिन बीते कुछ वर्षों से रूस का स्थान अमेरिका लेता आ रहा है ।

संदर्भ सूची:-

1. अंतरराष्ट्रीय संबंध

डॉ० बी०एल० फाड़िया

डॉ० कुलदीप फाड़िया

2. राजनीति शास्त्र विश्वकोष, बी०सी० नरूला

प्रकाश भाग-10

अर्जुन पब्लिशिंग हाउस

4831/24 प्रहलाद गली,

अंसारी रोड, दरियागंज,

नई दिल्ली- 110002

3. 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध, तृतीय संस्करण, पुष्पेशपंत, भूतपूर्व डीन

(अंतरराष्ट्रीय- जे०एन०यू०)

Tata McGraw Hill Education Private Limited

4. <https://hindi.news18.com/news/knowledge/know-about-supporter-countries-of-india-and-china>